इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां। उत्पादन लागत में वृद्धि होना एक कारण है।

(ख) कोयला, बिजली तथा रेल भाड़ा जैसे मुख्य आदानों की लागत में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। इन वृद्धियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए क्षमता उपयोग में वृद्धि करने, आधुनिकीकरण द्वारा ऊर्जा की खपत कम करने तथा इस उद्योग की उत्पादकता तथा तकनीकी आर्थिक निष्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Iron and Steel quota for Punjab

2176. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Government of Punjab had recently urged the Central Government to raise the ceiling fixed for iron and steel and pig iron quota for the State;

(b) if so, the yearly quantum of iron, steel and pig iron being given to Punjab;

(c) whether Central Government propose to provide adequate quantum of iron quota to Punjab State in view of the scarcity of raw materials in the State; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI M. L. FOTEDAR): (a) Yes, Sir. Government of Punjab had requested for increasing the quantum of iron and steel allocated and supplied to Punjab Small Industries & Export Corporation and the SSI sector during 1987-88.

(b) For 1987-88, 1,50,000 tonnes of pig iron was allocated on account of Punjab Small Industries & Export Corporation. For the first three quarters of 1987-88, 27,309 tonnes of steel have also been allocated in favour of Punjab Small Industries & Export Corporation.

(c) and (d) There is no system of fixation of State-wise quota for allotment of iron and steel materials. These are supplied on the basis of demand registered by the consumers. However, in the case of Small Scale Industries Corporations of States, allocations are made by Development Commissioner for Iron and Steel, based on the demands projected, the past performance in terms of offtake against offers made and the indigenous availability. Considering the increased demand for pig iron, the allocation for 1987-88 has been enhanced from 1,50,000 tonnes to 1,61,000 tonnes. In addition to allocations to the State Corporation, substantial quantities of iron and steel materials are distributed directly to consumers in the State of Punjab by the main producers.

खटीक जाति को अनुसूचित जाति के रूप में माना जाना

2177. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत खटिक समाज की अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया है कि दक्षिण भारत में खटिक जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाये,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1987 के अंग्रेजी दैनिक "हिन्दू" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर भारत में खटिक और सोनकर जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) जी, हां । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के संबंध में, इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ दक्षिणी राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची में खटीक समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । इसके अलावा संविधान की धारा 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखते हुये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है ;

(ग) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली की अनुसूचित जातियों की सूची में खटीक समुदाय को शामिल कर लिया गया है । अनुसूचित जातियों की वर्तमान सूची में सोनकर नहीं आते ।

Distribution of imported butter

2178. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the imported butter found unfit for human consumption has now been distributed to Dairy plants in organised and Cooperative Sectors, and if so, for what purpose it was used; and

(b) whether any irregularities in the distribution have been noticed, and if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Imported butter found unfit for human consumption has not been distributed by the National Dairy Development Board to Dairy plants in organised and Co-operative sector.

आवश्यक वस्तुओं के थोक/खुदरा मूल्य

2179. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के महीनेवार थोक और खुदरा मूल्य क्या थे ;

(ख) पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान विद्यमान मूल्यों की तुलना में यह मूल्य कितने हैं ; और

(ग) यदि मूल्यों में वृद्धि हुई है तो इस मूल्य वृद्धि का गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और निर्धारित आय वाले वर्ग के व्यक्तियों पर क्या असर पड़ा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना अनुबंध--I [देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुपत्र सं० 96] और II [देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुपत्र सं० 97] पर दिए गए विवरणों में दी गई है ;

(ग) पिछले 12 महीनों के दौरान कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है । गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों तथा नियत आय वर्ग के लोगों पर